भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 126
उत्तर देने की तारीखः 19.07.2021

शिक्षा पर कोविड का प्रभाव

†126 . **श्री सुधीर गुप्ता**:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने प्राथमिक से माध्यमिक और अन्य उच्च स्तर के पाठ्यकमों की शिक्षा पर कोविड-19 के किसी प्रभाव और छात्रों पर इसके प्रभाव पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ग) फीस में कमी, पाठ्यक्रम, शिक्षण घंटे के संबंध में प्रत्येक स्तर पर छात्रों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या यह भी सच हे कि कोविड -19 का आर्थिक प्रभाव अधिक बच्चों को रोजगार में धकेल सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या यह सच हे कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के कारण अगले वर्ष कई बच्चों के स्कूल वापस नहीं लौटने की आंशका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार की उक्त कारणों से बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने की कोई योजना हे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोविड-19 महामारी के फैलाव का शिक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है क्योंकि स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने अपने परिसर बंद कर दिए और राज्यों ने लाकडाउन के उपायों की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी सीमाएं बंद कर दीं। इससे शिक्षा बाधित हुई जिसके परिणामस्वरूप देश में शिक्षा प्रणाली बाधित हुई।

केंद्र सरकार शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए पहलों के संबंध में दिशा-निर्देशों और बैठक के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सलाह दे रही है। अब तक जारी किए गए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

- **प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए दिशानिर्देश**:
  https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Migrant%20labour%20guideline.pdf
- स्कूल न जाने वाले बच्चों और अधिगम संबंधी हानि को कम करने के लिए दिशानिर्देश: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/guidelines_oosc.pdf.

- डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञाता दिशानिर्देश: https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf
- सतत अधिगम के लिए अधिगम संवर्धन दिशानिर्देश : https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Learning_%20Enhancement_Guidelines.pdf
- **स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कोविड**-19 **संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा एसओपी /दिशानिर्देश**: https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools.pdf
- **स्कूल शिक्षा के लिए कोविड कार्य योजना: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने** 4 **मई**, 2021 **के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कोविड कार्य योजना साझा की है।**
- **जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी)-आवासीय विद्यालयों के लिए दिशानिर्देश** : https://drive.google.com/file/d/1LAc4iKQTqTJkNVDGc5glEDsrDGdAXwC8/view,
- **अभिभावकों के लिए दिशानिर्देश: अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए दिशानिर्देश**
- सीडब्ल्यूएसएन के लिए ई-कंटेंट: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए ई-कंटेंट संबंधी दिशानिर्देश
- सीबीएसई योग्यता-आधारित मूल्यांकन रूपरेखा: सीबीएसई ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से दसवीं कक्षा के लिए एक योग्यता-आधारित मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की है। यह एनईपी 2020 की सिफारिशों पर आधारित है और इससे परीक्षा के तनाव को कम करने में सहायता होगी तथा यह छात्रों में केवल सामग्री ज्ञान के बजाय दक्षता विकसित करने की ओर लक्षित है।
- **अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) दिशानिर्देश**: https://ncte.gov.in/WebAdminFiles/RecentAnnouncement/0_20_08_2020_637335320672297662.pdf

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने समय-समय पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 के फैलाव को रोकने और अन्य शैक्षणिक संबंधित मामलों के लिए नोटिस / सलाह भी जारी की है। यूजीसी ने परिसरों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित हैं। यूजीसी ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के संबंध में दिनांक 06.07.2020 को एक पत्र भी जारी किया है। यूजीसी ने इस पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए किए जाने वाले उपायों के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा जारी विस्तृत प्रक्रिया के बारे में सूचित किया।

ग) : शुल्क में कमी का विषय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में है। योगात्मक परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने के लिए, सीबीएसई ने कक्षा IX से XII के लिए बोर्ड / वार्षिक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को लगभग 30 प्रतिशत की सीमा तक युक्तिसंगत बनाकर आमने-सामने अध्यापन अधिगम के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन शिक्षण समय के संबंध में प्रज्ञाता दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल खुलने के बाद कक्षा में पढ़ाने के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यूजीसी ने 27.05.2020 को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर वार्षिक सेमेस्टर शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया और यदि संभव हो, तो स्थिति सामान्य होने तक छात्रों को वैकल्पिक भुगतान विकल्पों को मुहैया कराने पर विचार कर सकते हैं। एक अन्य पत्र दिनांक 17.12.2020 को विश्वविद्यालयों द्वारा फीस वापस करने और दस्तावेजों को न रखने के संबंध में जारी किया गया था। ये पत्र यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

भारत में कोविड-19 महामारी से संबंधित उभरती स्थिति को देखते हुए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। वहीं विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्धारित प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सितंबर, 2020 के अंत तक ऑफलाइन (पेन और पेपर)/ऑनलाइन/मिश्रित (ऑनलाइन + ऑफलाइन) मोड में परीक्षाएं पूरी करें। इन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि लॉकडाउन और संबंधित कारकों के कारण माता-पिता को होने वाली वित्तीय कठिनाई से बचने के लिए, इस सत्र के लिए एक विशेष मामले के रूप में छात्रों के सभी प्रवेश/प्रवास रद्द करने के कारण 30.11.2020 तक शुल्क की पूरी वापसी की जाएगी। तत्पश्चात, 31.12.2020 तक प्रवेश रद्द/वापस लेने पर, एक छात्र से एकत्र किया गया पूरा शुल्क प्रसंस्करण शुल्क के रूप में, जो 1000 रु/ - से अधिक न हो, की कटौती के बाद पूरी तरह से वापस कर दिया जाता है। इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों के इस बैच के नुकसान की भरपाई के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-2022 के लिए 6-दिवसीय सप्ताह के पैटर्न का पालन कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे बाद के वर्षों में अवकाश/छुट्टियों को कम करके शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में देरी की भरपाई करें ताकि छात्रों के इस बैच को डिग्री प्रदान करने के लिए उन्हें अपना अंतिम परिणाम समय पर प्राप्त हो सके।

(घ) से (ड.) : कोविड-19 महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई परामर्श किए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किये हैं कि स्कूल जाने वाले छात्र कोविड -19 महामारी के दौरान अपनी पढ़ाई में पीछे न रहें। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए ड्रॉपआउट की संख्या को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना / मजबूत करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, आवासीय विद्यालयों / छात्रावासों की स्थापना, मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन अभियान, आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास / आवासीय शिविर आदि शामिल हैं। स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, कोविड महामारी के कारण, चूंकि स्कूल बंद थे, प्राथमिक स्तर पर सभी नामांकित बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया है जिसमें खाद्यान्न और दालों का सूखा राशन आदि और खाना पकाने की लागत सम्मिलित है ।

च) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की गुणवत्ता और समानता के साथ शिक्षा तक पहुँच हो और देश में स्कूली शिक्षा पर महामारी का प्रभाव कम हो, स्कूल शिक्षा विभाग ने 7 जनवरी, 2021 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार और जारी किए हैं। अन्य के साथ दिशा-निर्देशों में, 6-18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता पैदा करना, स्कूल बंद होने पर छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निरंतर शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन), स्कूल फिर से खोलने पर छात्र सहायता और शिक्षक क्षमता निर्माण शामिल है। दिशानिर्देशों का लिंक है

https:/ /www.education.gov.in/sites/upload-files/mhrd/files/gaidelines-oosc.pdf.

4 मई 2021 को एक व्यापक कोविड कार्य योजना तैयार की गई और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई। कार्य योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ड्रॉप आउट को रोकने, स्कूली बच्चों का पता लगाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए मार्गदर्शन शामिल है। इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को संकलित करने और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया है - PRABANDH पोर्टल (http://samagrashiksha.in)। ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड किए गए पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों (ओओएससी) और एसटीसी की बच्चा-वार जानकारी को मान्य करने की आवश्यकता हैसाथ ही, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में पढ़ रहे स्कूल से बाहर के बच्चों के सीखने के अंतराल को पाटने के लिए ब्रिज कोर्स मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), ने वर्तमान कोविड -19 महामारी की स्थिति का संज्ञान लिया है जिसके कारण कई बच्चों ने एक को खो दिया है, और कुछ मामलों में, इस घातक वायरस के कारण माता-पिता दोनों को और संकटग्रस्त और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में, सचिव डीओएसईएल, एमओई और सचिव, एमडब्ल्यूसीडी से दिनांक 16.06.2021 को एक संयुक्त पत्र सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया है।

******